PEASANT MOVEMENTS(PART-3)

FOR P.G.SEM-3,CC-13,UNIT-3

BY:ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA.

तीस के दशक में कृषक आंदोलन

- इस दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन से किसान आंदोलन संबद्ध हो गया। कांग्रेस ने कर न देने संबंधी आंदोलन शुरू किया जिसका किसानों ने समर्थन किया।
- बंगाल के क्षेत्रों में किसानों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और मिदनापुर जिले में गैरकानूनी नमक बनाया ।
- 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के कार्यक्रम प्रस्तुत हुए।

तीस के दशक में कृषक आंदोलन

- 1937- 38 में **बिहार** में '**बकाश्त आंदोलन**' शुरू हुआ। बकाश्त का अर्थ है-स्वयं का जोता हुआ। बकाश्त भूमि जिले के जमींदार काश्तकारों को विभिन्न दर पर प्रतिवर्ष किराए पर देते थे ।बकाश्त किसानों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं थे इसलिए वे कभी भी जमीन से बेदखल कर दिए जाते थे।1937ई. के पश्चात से किसान सभा ने इस बेदखली का विरोध किया । 1946 ई.में मामला अधिक जोर पकड़ने लगा और मुंगेर, शाहाबाद, दरभंगा ,भागलपुर आदि जगहों में जमींदारों एंव काश्तकारों में जमकर संघर्ष हुआ।

तेभागा आंदोलन(1946-47)

- बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के किसानों का यह सबसे प्रबल आंदोलन था।सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा ने तेभागा संबंधित **फ्लाउड कमीशन** की सिफारिश को लागू करवाने के लिए जन संघर्ष का आह्वान किया। सिफारिश यह थी की जोतदारो से लगान पर ली गई जमीन पर काम करने वाले बटाईदारों(बरगादारों,भागचासी या अधियारों) को फसल का आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलने के स्थान पर **दो- तिहाई** हिस्सा दिया जाए।

तेभागा आंदोलन

- तेभागा के मांग से प्रारंभ हुए इस आंदोलन ने जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ।बंगाल के साम्यवादी नेताओं ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। यह आंदोलन बंगाल के 19 जिलों में फैला। स्वतंत्रता के बाद भी आंदोलन चलता रहा फलतः1949 ई. के **वर्गादार अधिनियम** को पारित कर किसानों को सहूलियत दी गयी।

अखिल भारतीय किसान सभा का गठन

- 1920 ई.तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हेतु प्रयास तेज हुए ।फलस्वरूप **1936** में **अखिल भारतीय किसान सभा** का गठन हुआ। **स्वामी सहजानंद सरस्वती** इसके **अध्यक्ष** बने और **एन .जी .रंगा महासचिव**। इसके पहले अधिवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। इस में भाग लेने वाले अन्य लोगों में राम मनोहर लोहिया ,सोहन सिंह जोश ,इंदूलाल याज्ञिक,जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव आदि लोग प्रमुख थे।

अखिल भारतीय किसान सभा का गठन

- किसान सभा का गठन कांग्रेस की पृथक इकाई के रूप में किया गया ।इसके दो प्रमुख कारण रहे -

1. किसान नेताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा था और वे देशी शोषकों अर्थात जमींदारों एवं ताल्लुकेदारों के विरुद्ध लगान अदा न करने के अभियान से आगे बढ़कर इसे किसान संघर्षों का रूप देना चाहते थे।
2. सविनय अवज्ञा आंदोलन से युवा विद्रोही,सामान्यतया वामपंथी

अखिल भारतीय किसान सभा का गठन

राजनीतिक संवर्गों की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ और स्वयं कांग्रेस भी अभिव्यक्ति का एक नया मार्ग खोजने लगी थी।सविनय अवज्ञा के असफल होने से लोग आंदोलन के नए तरीके खोजने में लगे थे और उन्हें किसानों के संगठन में उसके संकेत मिले।

अखिल भारतीय किसान सभा का गठन

- 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें किसानों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने को प्रेरित किया गया ।साथ ही आर्थिक शोषण से किसानों को संरक्षण, ऋण स्थगन,जमींदारी समाप्त करने, बेगार प्रथा समाप्त करने तथा लगान की राशि में कमी करने आदि की मांग रखी गई थी।
- किसान सभा ने **1936ई.** में कांग्रेस के **फैजपुर अधिवेशन** में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

कांग्रेस मंत्रिमंडल और किसान आंदोलन

- जब 1937 में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें गठित हुई तो किसानों की अपेक्षाएं और बढ़ गई थी और वे बहुत सी रियायतों की मांग करने लगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारें एक जमींदार विरोधी रेडिकल नीतियों को क्रियान्वित करने में हिचक रही थी। अतः1937- 38 के वर्ष की मुख्य विशेषता कांग्रेस नेतृत्व में किसान सभा के बीच वैचारिक टकराहट थी।

किसान आंदोलन का स्वरूप

- 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन स्थानीय हितों एवं तत्कालीन समस्याओं से जुड़े हुए थे।
- इन विद्रोह के पीछे जो असंतोष छिपा था उसका एक प्रमुख कारण आर्थिक शोषण था। इस शोषण के खिलाफ अंग्रेजों, भारतीय जमींदारों, प्रतिष्ठित शासक वर्ग और महाजनों के प्रति विद्रोह हुआ।
- इन आंदोलनों की दृष्टि व्यापक नहीं थी। ये अपने तत्कालिक शोषण करता के खिलाफ एकजुट हुए ।

किसान आंदोलन का स्वरूप

- इनका नेतृत्व करता स्थानीय समूह से होता था।
- विद्रोह में मूलभूत परिवर्तन की कल्पना नहीं की गई बल्कि इनका स्वरूप सुधारवादी एंव पुनःस्थापना से जुड़े प्रवृत्तियों से युक्त था।
- इन कृषक आंदोलन में हिंसा एवं बल का प्रयोग हुआ।
- बीसवीं शताब्दी के किसान आंदोलन अपने स्वरूप में 19वीं शताब्दी के आंदोलन से भिन्नता लिए हुए था।

किसान आंदोलन का स्वरूप

- इस समय आंदोलन अधिक व्यापक और विस्तृत हो गई ।अब किसान आंदोलनों में आर्थिक मांगों के साथ-साथ राजनीतिक मांगे भी शामिल हो गई।
- बीसवीं सदी के किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ने लगे।
- इन आंदोलनों का नेतृत्व प्रायः प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता द्वारा किया गया ।साथ ही में किसान संगठनों के माध्यम से भी संचालित हुए।

किसान आंदोलन का स्वरूप

- इन आंदोलनों में हिंसा का तत्व गौण हो गया और अब ये आंदोलन आधुनिक राजनीतिक पद्धतियों के माध्यम से चलाए जाने लगे जैसे सत्याग्रह ,धरना गिरफ्तारियां आदि
- प्रायः किसान आंदोलन का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष रहा।

किसान आंदोलन का परिणाम

- किसान आंदोलन ने परंपरागत जमींदारी व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी शासन की जड़े खोद दी |वस्तुत: इन आंदोलनों ने ऐसा माहौल तैयार किया जिससे राष्ट्रीय आँदोलन के दौरान राजनीतिक दलों में कृषि सुधार भी एक प्रमुख मांग बन गई|
- किसान आंदोलनों ने लोगों में जागृति लाने का कार्य किया| अनेक किसान संगठन स्थापित हुए जिन्होंने न केवल किसान आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन को भी गति प्रदान की |

किसान आंदोलन के संदर्भ में बहस

- 20 वीं सदी के किसान आंदोलन का संबंध में कुछ विवाद है ।कुछ इतिहासकारों ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि कृषक आंदोलन में धनी कृषकों का ही वर्चस्व था और इसलिए इन आंदोलनों में राष्ट्रवादी रुझान देखा गया। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद एक बुर्जुवा दृष्टिकोण होता है और इसका आधार बुर्जुवा वर्ग ही हो सकता है।

किंतु **पीटर हार्डीमन** ने इसका खंडन किया है और बताया है कि उस समय किसानों की मुख्य लड़ाई औपनिवेशिक शोषण के विरूद्‌ध थी।

किसान आंदोलन के संदर्भ में बहस

इसलिए उन्होंने तत्कालिक रूप में वर्गीय हितों की अनदेखी करते हुए भी राष्ट्रीय आंदोलन भागीदारी निभाई।

हार्डी मन एवं **ज्ञान पांडे** ने अपने विस्तृत शोधों के पश्चात यह स्थापित किया है कि आंदोलन का उभार निचले स्तर से भी होता रहा। किंतु कृषक ऊपरी स्तर के एक नेता को इसलिए ढूंढ लेते थे ताकि वह वार्ता एवं समझौता के जरिए कुछ विशेष रियायतें दिलवा सके।